[श्री सभापति]

Question Hour. Yesterday, we had a new experiment and Shri Sukhendu Sekhar Ray presided over Question Hour. He successfully conducted the proceedings. ...*(Interruptions)*...

SHRI JAIRAM RAMESH (Karnataka): We will miss you, Sir. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: You will never miss me. I am there in my Chamber. ...*(Interruptions)*...

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.*)

Need to formulate a comprehensive scheme to stop Child labour

श्री पी.एल. पुनिया (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाषति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने का अवसर दिया है। यह विषय चाइल्ड लेबर को रोकने और इससे जुड़ी समस्याओं से संबंधित है। हर वर्ष 12 जून को, "बाल श्रम विरोधी दिवस" के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाता है। हम लोग बाल श्रम को रोकने के लिए संकल्प भी लेते हैं। ILO की रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में 15 करोड़ 20 लाख चाइल्ड लेबर हैं। हिन्दुस्तान में करीब 7 से 8 करोड़ बच्चे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से वंचित रहते हैं। उनमें से लगभग 1 करोड़ बच्चे मजदूरी कर रहे हैं।

महोदय, इसके अतिरिक्त हर साल हजारों बच्चे ट्रैफिकिंग के जरिए नेपाल और बंगलादेश से भी भारत में लाए जा रहे हैं। इन बच्चों की कीमत तो जानवरों से भी कम होती है। घरेलू बाल श्रमिकों में बालिकाओं की संख्या सबसे ज्यादा है और कारखानों में बालकों की संख्या सबसे ज्यादा है। भारत में बाल श्रमिकों के उत्थान के लिए कई योजनाएं चल रही है और कई कानून भी बने हैं, लेकिन फिर भी इस पर पूरी तरह से प्रतिबन्ध नही लग पा रहा है। जिस उम्र में बच्चों के हाथों में कलम और किताब होनी चाहिए उस उम्र में ये बच्चे मजदूरी करके अपना पेट पालने को मजबूर हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि बाल श्रमिकों के उत्थान के लिए व्यापक कार्य-योजना बनाई जाए। बाल मजदूरी से मुक्ति के बाद उनके पुनर्वास, शिक्षा और मुख्य-धारा में लाने के लिए बनी योजनाओं को सही तरीके से लागू किया जाए, धन्यवाद।

श्रीमती कहकशां परवीन : महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करती हूं।

†**محترمہ کہکشاں پروین (بہار)** : مہودے، میں مانئے ممبر کے ذریعے اٹھائے گئے موضوع سے خود کو سمبدّھ کرتی ہوں۔

†Transliteration in Urdu Script.

श्री रवि प्रकाश वर्मा (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री राजमणि पटेल (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री मोतीलाल वोरा (छत्तीसगढ़): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

SHRI JOSE K. MANI (Kerala): Sir, I also associate myself with what the hon. Member has said.

श्री उपसभापति: माननीय सदस्यगण, मैं डा.सस्मित पात्रा को बुलाऊं, इससे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि श्रीमती सरोजिनी हेम्ब्रम जी ने आज संथाली में बोला। बड़ी तादाद में जो आदिवासी भाई इस भाषा को बोलते हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत प्रसन्नता का दिन है, जैसी भावना माननीय चेयरमैन साहब ने भी व्यक्त की। चूंकि मैं उस इलाके में लम्बे समय से रहा हूं, इसलिए मेरे लिए भी यह बेहद प्रसन्नता की बात है।

डा. सस्मित पात्रा जी।

Need for Special Focus Status to States facing natural disasters

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Mr. Deputy Chairman, Sir, I stand to demand Special Focus Status for the States facing natural calamities. And, I will make a case for it in my submission.

The United Nations Office for Disaster Risk Reduction, in its report Economic Losses and Poverty Disasters, 1998-2017, states that India suffered an economic loss of approximately 79.5 billion US dollars, which comes to around five lakh seventy thousand crores of rupees, due to climate-related disasters in the last twenty years.

Sir, with reference to this, I would like to give a simple fact about Odisha in terms of climate disasters as well. On August 6th, 2019, hon. Chief Minister, Shri Naveen Patnaik ji, released a Damage Assessment Report on the cyclone Fani, which devasted Odisha this year. The Report said that the total damage and loss was to the tune of rupees twenty-four thousand crores, and the recovery needed rupees thirty thousand